योजना संकलन: सितम्बर 2018

रोजगार और स्वरोजगार

द्वारा संचालित :

ग्रेडअप

प्रस्तावना

योजना, सितंबर, 2018: रोजगार एवं स्व रोजगार

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (CSE) में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उत्तर लेखन की सुदृढ़ शैली के महत्व से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। इस दृष्टिकोण से योजना जैसी पत्रिकाएं आवश्यक हो गई हैं। यह पत्रिका प्रमुख बिंदुओं, आंकड़ों, तथ्यों, और वक्तव्यों का एक भंडार है जिसका उपयोग अच्छे अंक अर्जित करने में किया जा सकता है। कई बार, निबंध अथवा सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों में योजना से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह पत्रिका आपको किसी मुद्दे से संबंधित लगभग सभी विश्लेषणात्मक पहलुओं से जुड़े विशिष्ट विषयों की अच्छी, विस्तृत और संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। यह आपको मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करती है जो दिन प्रतिदिन अधिक विश्लेषणात्मक होते जा रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा में भी, हमें योजना से लिए गए अनेक वक्तव्य मिलते हैं।

gradeup

यह सब योजना जैसी पत्रिकाओं को पढ़ने की अनिवार्यता को दर्शाता है। यद्यपि पूरी पत्रिका को पढ़ने के अपने ही लाभ हैं, लेकिन हमें उपलब्ध समय को भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिए, आप पत्रिका के सारांश को पढ़ सकते हैं जिसमें जानकारी सुव्यवस्थित ढ़ंग से प्रस्तुत है जिसे आसानी से याद रखा जा सकता है और परीक्षा में सरलता पूर्वक लिखा जा सकता है। हमारे द्वारा प्रस्तुत यह पत्रिका उस दिशा में एक प्रयास मात्र है। यह आपको विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं और उनका विश्लेषण प्रदान करेगा, जिसे किसी परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

प्रस्तुत अंक **योजना- सितंबर, 2018** संस्करण का सारांश है जो भारत के विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार प्रस्तुत करता है। हमारा मानना है कि यह उम्मीदवारों के लिए उच्चतम प्रतिफल सुनिश्चित करने में बेहद लाभदायक सिद्ध होगा।

हमारी ओर से शुभकामनाएं ☺

विषय सूची

1. रोजगार संबंधित विश्वसनीय आंकड़े: समय की आवश्यकता
2. आजीविका विकास और विविधीकरण
3. शहरी क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसरों का सृजन
4. नवाचार और उद्यमिता: रोजगार की कुंजी
5. जनसांख्यिकीय लाभ के उपयोग
6. एम.एस.एम.ई: वृद्धि और विकास के नए साधन

gradeup

रोजगार संबंधित विश्वसनीय आंकड़े: समय की आवश्यकता

- परिचय
- रोजगार के विश्वसनीय आंकड़ों की स्थिति
- रोजगार आंकड़ों के लिए प्रयास
- रोजगार सृजन अनुमान: वेतन भुगतान (पेरोल) और असंगठित क्षेत्र
- स्व रोजगार की स्थिति
- निष्कर्ष

परिचय

- भारत की युवा और बढ़ती आबादी के लिए बड़े पैमाने पर नौकरियों की आवश्यकता है जो भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े खोजने की आवश्यकता पर जोर देती है।
- इस आवश्यकता को हालांकि असंगठित क्षेत्र में 80% रोजगार द्वारा चुनौती दी गई है, जिसका सहज आकलन अत्यंत मुश्किल है और प्रदान की गई नौकरी की गुणवत्ता आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है।
- भारत की मौजूदा जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार, 10-12 मिलियन लोग प्रत्येक वर्ष नौकरी के बाजार में प्रवेश करते हैं। मौजूदा उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं, कि अर्थव्यवस्था ने पर्याप्त रोजगार पैदा किए हैं, जो वास्तविकता नहीं है, वास्तव में पिछले वर्षों से युवाओं को बड़े पैमाने पर संचित कार्य दिए गए हैं।

रोजगार के विश्वसनीय आंकड़ों की स्थिति

- सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी रोजगार सर्वेक्षण आंकड़े सबसे विश्वसनीय आधिकारिक स्रोत माने जाते हैं।
- एन.एस.एस.ओ द्वारा किए गए रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण इस संदर्भ में सबसे व्यापक सर्वेक्षण है, लेकिन यह पिछली बार वित्त वर्ष 2011-12 में किए गए थे। जिसका अर्थ है कि आंकड़े 6 वर्षों से अधिक पुराने हैं।
- वर्ष 2015-16 में श्रम ब्यूरो द्वारा किया गया वार्षिक श्रम सर्वेक्षण भी कुछ हद तक पुराना है।
- श्रम ब्यूरो के वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही में हालिया तिमाही सर्वेक्षण में केवल 8 क्षेत्र शामिल हैं जो अर्थव्यवस्था के 15% से भी कम है।

रोजगार आंकड़ों के लिए प्रयास

- सरकारी रोजगार आंकड़ों में शून्यता को देखते हुए, CMIE-BSE ने त्रि-वार्षिक रोजगार रिपोर्ट तैयार करके इसे भरने का प्रयास किया है। लेकिन सुरजीत भल्ला और तिरथा दास के अनुसार, CMIE के आंकड़े गैर भरोसेमंद है।
- इन विशाल आंकड़ों के अंतर को देखते हुए, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स ने जुलाई, 2017 में रोजगार आंकड़ों पर वार्षिक सर्वेक्षण की सिफारिश की जो अब

gradeup

कार्यान्वित की गयी है। रोजगार पर पहला एन.एस.एस.ओ पारिवारिक सर्वेक्षण जो वर्ष 2019 में जारी किया जाएगा, इस क्षेत्र में सभी आवश्यक विवादों पर विराम लगाएगा ।

<u>रोजगार सृजन: अनुमान</u>

संगठित क्षेत्र- पेरोल रिपोर्टिंग:

- पेरोल रिपोर्टिंग औपचारिक नौकरियों की संख्या और मासिक आधार पर इसमें वृद्धि को मापती है।
- भारतीय औपचारिक क्षेत्र में ई.पी.एफ.ओ के पेरोल आंकड़ों के अनुसार, सितंबर, 2017 से अप्रैल, 2018 तक 41 लाख औपचारिक नौकरियों का सृजन किया गया था।
- ई.पी.एफ.ओ के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017-18 में सृजित नौकरियों की संख्या 5.5 मिलियन थी, जिसमें 2016-17 में 4.5 मिलियन शामिल की गई थी।

असंगठित क्षेत्र:

- असंगठित क्षेत्र में भारतीय श्रम बल का 80% से अधिक भाग शामिल है।
- नई अर्थव्यवस्था ने ओला/उबर में चालक भागीदारों या डिलीवरी पेशेवरों या पेशेवर घरेलू सेवा एग्रीगेटर्स जैसे सदस्यता-आधारित रोजगार बनाए हैं। उदाहरण के लिए, पिछले चार वर्षों में कैब व्यवसाय ने 2.2 मिलियन से अधिक नौकरियां पैदा की हैं और अर्बन क्लैप तथा क्विकर जैसी सेवाओं में व्यक्तिगत रूप से 2.5 मिलियन से अधिक पेशेवर पंजीकृत हैं।
- लेखाधिकारी (सी.ए.), कंपनी सचिव, वकील और अन्य पेशेवर जो हर वर्ष कार्यबल में शामिल होते हैं, वह भी अतिरिक्त कर्मचारियों को सहायक और अन्य सेवा प्रदाताओं के रूप में भी नियुक्त करते हैं। इन संख्याओं को कहीं भी नहीं जोड़ा जाता है।
- इसी प्रकार, ट्रक चालक, ऑटो रिक्शा चालक, सड़क किनारे स्थित भोजनालय, पर्यटन संबंधित श्रमिक, ग्रामीण मंडियों और बाजारों आदि में नियोजित लोगों को दर्ज नहीं किया गया है।
- जब तक इन अनौपचारिक क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अनुमान नहीं बनाए जाते, पिछले चार वर्षों में रोजगार की स्थिति या नौकरी के सृजन की सीमा के बारे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना काफी भ्रामक होगा।

<u>स्व रोजगार की स्थिति</u>

- पिछले चार वर्षों में स्व-नियोजित रोजगार की संख्या काफी बढ़ गई है। मुद्रा (MUDRA) ऋण उन प्रमुख योजनाओं में से एक है जो उद्यमियों को पूरे भारत में स्व-रोजगार और नौकरी के सृजन की दिशा में मदद कर रही है।
- पिछले तीन वर्षों में, 12.27 करोड़ ऋण वितरित किए गए हैं। इनमें से 74% महिला उधारकर्ता हैं। इनमें से प्रत्येक ऋण ने नई नौकरियों का सृजन किया है।
- यहां तक कि अगर हम प्रति मुद्रा (MUDRA) ऋण में नई नौकरियों की संख्या को सीमित करते हैं और यह मानते हैं कि पुनरावृत्त उधारकर्ताओं ने नई नौकरियां नहीं पैदा की हैं, तो हमें केवल मुद्रा (MUDRA) योजना के तहत 6 करोड़ या 60 मिलियन नौकरियां सृजित होने का आकलन प्राप्त होता है।

gradeup

निष्कर्ष:

- इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पिछले चार वर्षों में रोजगार सृजन देखा गया है और नौकरियों की मांग कार्यबल के लिए नए प्रवेशकों की आपूर्ति से कम नहीं है।
- यह वृद्धि वास्तविक वेतन में वृद्धि में भी दिखाई देती है। लेकिन यहां, आंकड़े एक समस्या है क्योंकि यह शहरी क्षेत्र के लिए उपलब्ध नहीं है लेकिन वर्ष 2014-18 के लिए कृषि और गैर-कृषि व्यवसायों में वार्षिक औसत दैनिक मजदूरी दर पर श्रम ब्यूरो के आंकड़े दर्शाते हैं कि प्लंबर को छोड़कर सभी वर्गों के लिए वास्तविक मजदूरी बढ़ी है।

gradeup

आजीविका विकास और विविधीकरण

- परिचय
- ग्रामीण विकास के लिए व्यय
- गरीब परिवारों पर विशेष ध्यान
- आजीविका विविधीकरण पर विशेष ध्यान
- ग्रामीण निर्धनता
- निष्कर्ष

परिचय:

- चूंकि सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी) प्रत्यक्ष तौर पर सामने आते हैं, अत: निर्धनता बहु-आयामी है और इसलिए कई हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है। हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र का आधा भाग और सेवा क्षेत्र का एक तिहाई भाग पहले से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। आजीविका विकास और विविधीकरण के माध्यम से आय एवं रोजगार प्रत्यक्ष तौर पर आगे बढ़ रहा है।
- पिछले 4 वर्षों में ग्रामीण अवसंरचना में सुधार, आजीविका में विविधता, गरीबी को कम करना और ग्रामीण विकास विभाग के कार्यक्रमों के आवंटन के मामले में गरीब परिवारों के कल्याण में सुधार हेतु वित्तीय संसाधनों में काफी कदम उठाए गए हैं।

gradeup

ग्रामीण विकास के लिए व्यय:

- वर्ष 2017-18 में वार्षिक व्यय वर्ष 2012-13 की अपेक्षाकृत दोगुने से अधिक है।
- गैर-हिमालयी राज्यों के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पी.एम.ए.ई-जी), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी), डी.ए.वाई-एन.आर.एल.एम इत्यादि जैसे कार्यक्रमों के तहत हिमालयी राज्यों में साझाकरण पैटर्न 60:40 और 90:10 हो गया है।
- वर्ष 2017-18 से, आवास कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त संसाधनों को अतिरिक्त बजट संसाधन (ई.बी.आर) के माध्यम से संघटित किया गया था। पी.एम.ए-ग्रामीण के लिए वर्ष 2017 से 2019 तक कुल 21,975 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजटीय फंड जुटाया गया है।
- 14वें वित्त आयोग पुरस्कारों के तहत निधि हस्तांतरण में 13वें वित्त आयोग के तहत आवंटन की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
- महिला एस.एच.जी द्वारा बैंक ऋण का लाभ उठाना एक अन्य कारक है। पिछले 5 वर्षों में महिला एस.एच.जी द्वारा बैंक ऋण के रूप में कुल 1.64 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।

- ग्रामीण निर्धनता कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट संसाधन प्रावधान के अलावा, स्वच्छ भारत मिशन पर जोर, कृषि मंत्रालय और अन्य अवसंरचना के आवंटन में वृद्धि और गरीबों के लिए आजीविका कार्यक्रम, ग्रामीण भारत को वित्तीय संसाधनों का कुल हस्तांतरण अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

<u>गरीब परिवारों पर विशेष ध्यान:</u>

- सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (SECC -2011) ने विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए साक्ष्य आधारित मानदंड प्रदान किए हैं।
- SECC का उपयोग उज्ज्वला के तहत एल.पी.जी गैस कनेक्शन के व्यवस्थापन, सौभाग्य के तहत नि:शुल्क घरेलू बिजली कनेक्शन, पी.एम.ए.वाई-जी के तहत लाभार्थियों और यहां तक कि हाल ही में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण के प्रबंधन के लिए किया गया है।
- इसका प्रयोग मनरेगा (MGNREGS) के तहत और डी.ए.वाई-एन.आर.एल.एम में श्रम बजट को अंतिम रूप देने के लिए भी किया जाता है।

<u>आजीविका विविधीकरण पर विशेष ध्यान:</u>

- ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रमों को आजीविका विकास और विविधीकरण के लिए संरेखित किया गया था। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:
  - 143 लाख हेक्टेयर भूमि पर जल संरक्षण कार्य उपलब्ध कराया गया|
  - एस.एच.जी महिलाओं से 1000 बैंक सखी और 773 बैंक मित्र प्रशिक्षित
  - 126 कृषि उत्पादक कंपनियों की स्थापना
  - आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत 449 वाहन
  - 4000 महिला एस.एच.जी द्वारा बनाए गए 9 लाख सोलर लैंप।
  - आवास योजना के तहत प्रशिक्षित 10949 राजमिस्त्री।
- मनरेगा (MGNREGS) ने स्थाई संपत्तियों और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया, और कृषि तालाबों, कुआ खुदाई, बकरी शाला इत्यादि जैसे व्यक्तिगत लाभ पैदा करने के लिए आजीविका प्रदान की। फल और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि और पिछले चार वर्षों में पशु संसाधनों के माध्यम से प्रमुख वृद्धि ग्रामीण आजीविका विकास और विविधीकरण पर विशेष जोर देने के कारण हुई है।
- ग्रामीण अवसंरचना के लिए, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) एक प्रमुख कार्यक्रम रहा है और पिछले 4 वर्षों में 1.69 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गई थीं। इसने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न किए हैं। सामान्य तौर पर ग्रामीण सड़कों के निर्माण की कुल लागत का एक चौथाई भाग रोजगार में योगदान देता है।
- 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं की रसद के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए) के विस्तार ने गरीब परिवारों में खाद्य सुरक्षा की सुविधा प्रदान की है।
- ग्रामीण प्रबंधन आनंद संस्थान (आई.आर.एम.ए) के मूल्यांकन अध्ययन ने गांवों में आय, उत्पादक परिसंपत्तियों और उद्यमों में वृद्धि की पुष्टि की है, जहां महिला एस.एच.जी डी.ए.वाई-एन.आर.एल.एम के तहत सक्रिय हैं।

<u>ग्रामीण निर्धनता:</u>

gradeup

ग्रामीण निर्धनता वास्तव में बहु-आयामी है और एक बड़े प्रभाव के लिए इसे एक साथ संबोधित करने की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में गरीब परिवारों के वास्तविक परिवर्तन के लिए ग्रामीण पहलों के अभिसरण की दिशा में प्रयास किए गए हैं।

परिवारों में निम्न तथ्यों की कमी :

- शिक्षा और कौशल की कमी।
- कुपोषण और बीमारी
- रोजगार के अवसरों की कमी
- सुरक्षित आवास की कमी
- सार्वजनिक सेवाओं तक सीमित पहुंच।
- बिचौलियों / भ्रष्टाचार / साहूकारों का शिकंजा
- महिलाओं / युवाओं / गरीब परिवारों के सामाजिक पूंजी संग्रह का न होना।

भौगोलिक क्षेत्रों की कमी:

- उत्पादन के लिए कम मूल्य - संकट।
- हिंसा / अपराध
- गैर सिंचित कृषि / मानसून की अनियमितताएं।
- बुनियादी अवसंरचनाओं- सड़कों, बिजली, और इंटरनेट की कमी
- बाजारों और नौकरियों तक पहुंच की कमी।
- गैर-कृषि अवसरों की कमी।

grndeup

<u>निष्कर्ष:</u>

इसलिए, दिए गए आंकड़ों और हस्तक्षेपों से यह स्पष्ट है कि महिला एस.एच.जी के लिए बैंक ऋण के बड़े पैमाने पर लाभ के साथ ग्रामीण निर्धनता को संबोधित करने हेतु उच्च वित्तीय संसाधनों ने आजीविका विविधीकरण और विकास के माध्यम से आय और रोजगार दोनों की वृद्धि में योगदान दिया गया है।

शहरी क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसरों का सृजन

- परिचय
- कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र
- प्रमुख जोखिमों की पहचान और निपटान
- आगे बढ़ने का मार्ग

परिचय:

- जनगणना 2011 के अनुसार, कुल जनसंख्या के 31% से अधिक लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते थे और अनुमान बताते हैं कि वर्ष 2050 तक यह 50% से अधिक हो जाएगा। जैसे-जैसे शहर अधिक बड़े और सघन हो जाएंगे, आजीविका मुहैया कराने का दबाव भी बढ़ता जाएगा।
- विनिर्माण और सेवा उद्योगों में बदलते तकनीकी परिदृश्य और कृषि के मशीनीकरण से शहरी क्षेत्रों में नौकरी की संभावनाओं में अधिक वृद्धि हो सकती है।
- अनुमान है कि अगले 2 दशकों में, शहरी भारत में लगभग 70% नई नौकरियों का सृजन होगा।

कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र

- राष्ट्रीय कौशल विकास योजना वर्ष 2009 में आरंभ की गई थी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी) की स्थापना वर्ष 2022 तक 150 मिलियन लोगों के कौशल विकास के आदेश के साथ की गई थी।
- एक सतत योजना निर्देश और कौशल दृष्टिकोण की आवश्यकता को देखते हुए, कौशल भारत मिशन वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इसके लक्ष्य को संशोधित करते हुए अब वर्ष 2022 तक 400 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करना है।
- कौशल पारिस्थितिक तंत्र को औपचारिक वित्तीय सेवाओं द्वारा पूरा किया जा रहा है जो स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। JAM+ संरचना, जिसमें जन धन (Jan Dhan), आधार (Aadhar) और मोबाइल (Mobile) आधारित सेवाएं शामिल हैं, ने वित्तीय समावेशन के निष्पादन को जन्म दिया।
- विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट से पता चला है कि वर्ष 2011 में वयस्क खाता धारकों की संख्या 35% से बढ़ी है और वर्ष 2014 में 53% बढ़कर वर्ष 2017 में 80% हो गई है।
- खाता धारकों में लिंग अंतर 83% पुरुषों तक कम हो गया है और अब 77% महिलाओं का भी खाता है।
- मुद्रा (MUDRA) ऋण लाभार्थियों में, महिलाओं का लगभग 75% हिस्सा है (विश्व बैंक, 2018)।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डी.ए.ई-एन.यू.एल.एम) निर्धन और कमजोर लोगों के लिए आजीविका अवसरों के सृजन की दिशा में कार्य कर रही है।

बहुआयामी आजीविका रणनीतियां:

- मिशन का लक्ष्य सर्वांगीण दृष्टिकोण के माध्यम से शहरी गरीबी को कम करना और आजीविका समृद्धि पर विशेष ध्यान देना है।
- मिशन के सामाजिक संघटन और संस्थागत विकास घटक तीन स्तरीय समुदाय संरचना: एस.एच.जी, क्षेत्रीय स्तर संघ और शहरी स्तर संघ के माध्यम से सामाजिक पूंजी का सृजन करते हैं।
- मिशन के तहत स्थापित शहरी आजीविका केंद्र (सी.एल.सी) शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर अनौपचारिक स्थानीय सेवा क्षेत्र को व्यवस्थित करने में सहायता करते हैं।
- कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति (ई.एस.टी.पी) घटक के माध्यम से रोजगार कौशल भारत मिशन के तहत बाजार प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रदान करता है।
- स्व रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी) शहरी गरीबों के वित्तीय समावेश पर केंद्रित है और सब्सिडी वाले ऋण के माध्यम से उनके सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन प्रदान करता है।
- शहरी गली विक्रेताओं के घटक के समर्थन का उद्देश्य गली विक्रेता अधिनियम 2014 के अनुसार सड़क विक्रेताओं की आजीविका की रक्षा करना है। इसके तहत उनके पेशे को वैधता मिली है।
- सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए लगभग 45% एस.एच.जी बैंक श्रृंखला ऋण का उपयोग किया गया है। मिशन ने अभी तक 25 लाख से अधिक आजीविकाओं का समर्थन किया है।

मिशन मूल्यांकन और नई पहल

- डी.ए.वाई-एन.यू.एल.एम के तहत ब्याज अनुदान के लिए एक वेब पोर्टल स्थापित करने के लिए एक प्रमुख पहल आरंभ की गई है।
- प्रशिक्षित उम्मीदवारों से सीधी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए पारस (पी.आर.ए.एस) नामक एक व्यवस्था पेश की गई है। मिशन के परिणाम मानकों के आधार पर राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रेरित करने के लिए स्पार्क नामक एक रैंकिंग प्रणाली शुरू की गई है।

gradeup

<u>प्रमुख जोखिमों की पहचान और निपटान</u>

- मिशन द्वारा संबोधित किए जाने वाले तीन प्रमुख राष्ट्रीय चुनौतियां हैं:
  - रोजगार की अनौपचारिक प्रकृति।
  - श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी।
  - कार्यान्वयन एजेंसियों की क्षमता पर प्रतिबंध।
- *शहरी अनौपचारिक कार्यबल को औपचारिक रूप देना:*
  - रुझान दर्शाते हैं कि देश में शहरीकरण की उच्च दर औपचारिकता की आनुपातिक उच्च दर के साथ नहीं है, शहरी क्षेत्रों में अधिक अनौपचारिक उद्यमों को जोड़ा जा रहा है।
  - डी.ए.वाई-एन.यू.एल.एम 2 पहलों के माध्यम से इस चुनौती को संबोधित कर रही है। पहली, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई) को अभिसरण में प्राथमिक शिक्षा पहचान (आर.पी.एल) के रूप में अंगीकृत किया गया है, जिसे अनौपचारिक रूप से कौशल हासिल करने वालों को पहचान दिलाने, प्रमाणित करने और औपचारिक रूप देने की व्यवस्था के रूप में अपनाया गया है।
  - दूसरी, शहरी आजीवका केंद्रों (CLCs) को स्वच्छंद सेवा प्रदाताओं का एक मजबूत डाटाबेस निर्माण पर एक नवीकृत ध्यान केंद्रण के साथ पुनर्जीवित किया गया है, जिससे उनकी सेवाएं मोबाइल ऐप्स आदि के माध्यम

से उपलब्ध कराई जा सकें। कई सी.एल.सी अनौपचारिक श्रमिकों का चयन करके उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं और नगरपालिका संविदा के माध्यम से उनके औपचारिक रोजगार को सुविधाजनक बना रहे हैं।

- *शहरी कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार*
  - भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 21 प्रतिशत अंक बढ़ सकती थी यदि काम करने की इच्छा व्यक्त करने वाली सभी महिलाएं ऐसा करने में सक्षम थीं।
  - डी.ए.वाई-एन.यू.एल.एम ने महिलाओं को एस.एच.जी में संगठित करके इस अंतर को कम किया है। लगभग 30 लाख महिलाओं को एस.एच.जी और उनके संघों में शामिल किया गया है।
  - 70% से अधिक प्रशिक्षित व्यक्ति, महिलाएं हैं।
- *स्थानीय निकायों का शहरी क्षमता निर्माण क्(यू.एल.बी)*
  - डी.ए.वाई-एन.यू.एल.एम के लिए शहरी स्थानीय निकाय प्रमुख कार्यान्वयन इकाइयां हैं। मंत्रालय ने रोजगार और स्व-रोजगार कार्यक्रमों सहित शहरी मिशनों को लागू करने और उन्हें शहरी गरीबों हेतु संवेदनशील बनाने के लिए क्षमता निर्माण हेतु एकीकृत क्षमता निर्माण कार्यक्रम (आई.सी.बी.पी) लॉन्च किया है।

<u>उन्नति की ओर अग्रसर:</u>

- अमृत, पी.एम.ए.वाई-यू, हृदय (एच.आर.आई.डी.ए.वाई) आदि जैसे मंत्रालय के विभिन्न मिशन शहरी क्षेत्रों में सार्थक पूंजी निवेश कर रहे हैं जो डी.ए.वाई-एन.यू.एल.एम के प्रयासों का पूरक है।
- जीवन का स्तर बढ़ने के साथ, ई-कॉमर्स डिलीवरी, ऑन-डिमांड टैक्सी सेवा, फिटनेस और कल्याण आदि जैसे नए क्षेत्र उभर रहे हैं और डी.ए.वाई-एन.यू.एल.एम इन क्षेत्रों से संबंधित कोर्सों को प्रोत्साहित कर रहा है।
- ऐसे कौशल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मांग पर पकड़ रखने के लिए, एन.एस.डी.सी ने प्रवासी कौशल विकास योजना शुरू की है और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं।

gradeup

नवाचार और उद्यमिता: रोजगार की कुंजी

भारतीय युवाओं के लिए अवसर पैदा करने की दिशा में चुनौतियां

- 15-29 साल के आयु वर्ग की लगभग 27% जनसंख्या के साथ दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी भारत की है। इस युवा शक्ति का उपयोग करके भारत दुनिया की कौशल राजधानी बन सकता है।
- लेकिन शिक्षा और कौशल के निम्न स्तर तथा पढ़ाई जारी न रखने की बढ़ती दरों से भारतीय युवाओं की रोजगार हासिल करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है।
- वे ज्यादातर निम्न कौशल वाली नौकरियों का चयन करते हैं और कई युवा बाद में कृषि, विनिर्माण एवं निर्माण में और परिवहन में कार्य करते हैं।
- बेरोजगारी दर में शैक्षिक योग्यता में वृद्धि के साथ बढ़ोत्तरी देखी गई है, अर्थात स्नातक और इससे उच्च स्तर की शिक्षा वाले लोगों के लिए यह 18.4% से अधिक है।
- युवाओं के रोजगार हासिल न कर पाने के कारणों में से एक है अधिकांश युवाओं का शिक्षा के सामान्य विषय वर्ग को प्राथमिकता देना, जबकि केवल 12.6% तकनीकी / पेशेवर शिक्षा का और 2.4% व्यावसायिक शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करते हैं।
- सुव्यवस्थित रोजगार को बढ़ाने की भी आवश्यकता है, जो वर्तमान में श्रम बल के लगभग 8% युवाओं को संगठित करता है।
- विद्यालयों को अधिगम संस्थानों के रूप में विकसित होना चाहिए जहां रोजगार के लिए अधिगम कौशल में रुचि विकसित करने हेतु कक्षा 6 से स्कूल पाठ्यक्रम में व्यावसायिक कौशल शामिल किया जाए।
- युवाओं को तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा का चयन करने में प्रोत्साहित करने और व्यावसायिक / तकनीकी शिक्षा हेतु शुल्क मुहैया कराने में सहायता करने की दरकार है क्योंकि इनमें से अधिकांश संस्थान निजी क्षेत्र के हैं और निम्न आय वर्ग के युवाओं की पहुंच से बाहर हैं।

कार्यबल के लिए नए उभरते अवसर:

- भारतीय श्रमिकों की संख्या वर्ष 2022 तक 600 मिलियन हो सकती है। यदि इस जनसांख्यिकीय आंकड़े को उत्पादक कार्यबल में परिवर्तित किया जाए तो जनसांख्यिकीय क्षमता जी.डी.पी वृद्धि को आसान बना सकती है।
- प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों की वृद्धि आजीविका को प्रभावित कर रही है और नौकरी के नए अवसरों का सृजन कर रही है। सड़क, नौपरिवहन, स्मार्ट शहरों, नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन इत्यादि जैसी अवसंरचनाओं में भारी निवेश को भी आकर्षित कर रही है।
- अटल इनोवेशन मिशन; महिला उद्यमिता पर विशेष ध्यान; मुद्रा (Mudra); स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया निम्न कौशल वाले ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी लाखों लोगों के लिए नौकरियों और आजीविका के अवसरों की उपलब्धता को प्रभावित कर रहे हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल, खुदरा, ऑटोमोबाइल और पर्यटन एवं अतिथि सेवा जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार पैदा करने की क्षमता है।
- यह विनिर्माण और सेवा अधारित विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली रोजगार रणनीति की मांग करता है।

gradeup

डिग्री के बजाय कौशल पर जोर देने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देना

- श्रम बाजारों को एक विरोधाभास का सामना करना पड़ रहा है, जहां किसी भी नौकरी के लिए बड़ी संख्या में आवेदक होते हैं और फिर भी नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की पूर्ति मुश्किल होती है।
- आज की तकनीक संचालित दुनिया में, यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि कौन से व्यवसाय में वृद्धि होगी और किसमें गिरावट आएगी, इसलिए प्रमुख चुनौती कामगारों को ऐसे कौशल में प्रशिक्षित करना है जो विशेष उद्योगों की जरूरतों को पूरा करते हुए व्यवसायों में हस्तांतरण योग्य हो।
- इसे द्वि-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है:
  - शिक्षण कौशल जो सभी व्यवसायों में स्थानांतरित होता है।
  - विशेष उद्योग के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशल प्रदान करना।
- प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में विकसित ज्ञान संबंधी कौशल कार्यस्थल पर कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के बेहतर शिक्षित विद्यार्थी तकनीकी कौशल सहित विविध कौशल सीखने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं।
- स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाना बच्चों को हाई स्कूल स्तर में विकल्प प्रदान करता है। कुछ देशों ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, नीदरलैंड्स, स्लोवाकिया गणराज्य और स्विट्ज़रलैंड में स्कूल आधारित शिक्षा को कार्य आधारित शिक्षा से जोड़ा गया है।
- माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेज स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने के लिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केरल जैसे राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि ये एक छात्र को सामान्य शिक्षा हासिल करने के साथ-साथ स्नातक स्तर के समय तक नौकरी, बाजार के लिए तैयार करते हैं।
- राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संरेखित करने और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क वाले स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संरेखण की आवश्यकता है।
- अटल टिंकरिंग लैब्स छात्रों में नई सोच की आदत विकसित करने और हस्तांतरणीय कौशल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

रोजगार सृजन की अधिकतम क्षमता वाले क्षेत्र

- सेवा क्षेत्र ने नौकरी के अवसरों की तलाश में लगे युवा श्रमिकों के एक बड़े समूह को प्रभावित करने वाली डिजिटल तकनीक को अपनाया है।
- बिग डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअल रिएलिटी, ब्लॉक चेन और वैद्युत वाहन के क्षेत्र भविष्य में अत्यधिक कुशल और उच्च वेतन वाली नौकरियां उत्पन्न करेंगे।
- कम शिक्षित और कम कुशल श्रमिकों के बड़े समूह के लिए कपड़े और चमड़े; पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी; और निर्माण क्षेत्र में अवसर हैं।
- स्टार्ट-अप इंडिया; मुद्रा; स्टैंड-अप इंडिया; स्वच्छ भारत जैसी सरकारी पहल कम कुशल श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं।

gradeup

<u>उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना</u>

- रोजगार के अवसर पैदा करना, नवाचार को बढ़ावा देना उद्यमशीलता का एक महत्वपूर्ण कारक है और इससे विकास को प्रोत्साहन मिला है।
- जनसंख्या के लाभ का उपयोग करना और निम्न कौशल और शिक्षा के बावजूद लोगों के पास आजीविका के अवसर सुनिश्चित करना जरूरी है।
- वर्ष 2014 से सरकार की पहल उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के लिए लोगों की सोच को बदल रही हैं। ऋण प्राप्ति, बाजार से संपर्क, नेटवर्क और सलाहकारों के संदर्भ में पहले की चुनौतियों को स्टार्ट अप इंडिया, ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा और अटल इनोवेशन मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से दूर किया जा रहा है।
- शिक्षा, ई-कॉमर्स, वित्तीय सेवाओं, आई.टी.ई.एस आदि के क्षेत्र में तकनीकी आधारित स्टार्ट-अप की संख्या बढ़ रही है, जिससे भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र बन रहा है। उदाहरण बायजूस ऐप केवल 3 वर्षों में सफल हो गया।
- टेली मेडिसिन सलाह ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावहारिक हो गई है।

<u>अटल इनोवेशन मिशन की भूमिका</u>

- अटल इनोवेशन मिशन देश भर में उद्यमिता का एक पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए नीति आयोग के तहत भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जो नौकरी के सृजनकर्ताओं के निर्माण को सक्षम बनाएगा।
- ए.आई.एम छात्र नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना कर रहा है और इसने अटल न्यू चैलेंजेस शुरू किया है जो राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक प्रभाव वाले उत्पादों को प्रोत्साहित करेगा।
- अभी तक भारत में 650+ जिलों में 5441 अटल टिंकरिंग लैब चुनी गई हैं और कृषि, शहरी आवास, पेयजल और स्वच्छता में 24+ अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस का शुभारंभ किया गया है।

gradeup

जनसांख्यिकीय लाभ के उपयोग

परिचय

- भारत जनसांख्यिकीय परिवर्तन से गुज़र रहा है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार, वर्ष 1950 से पहली बार विकसित देशों की संयुक्त कार्यशील आयु (डब्लू.ए) वाली आबादी चीन और रूस दोनों की कार्यशील आयु वाली आबादी में व्यक्तिगत रूप से 20% की गिरावट के साथ कमी का सामना कर रही थी।
- वहीं दूसरी ओर, वर्तमान में युवा वर्ग में 28% आबादी के साथ भारत अपनी कार्यशील आयु वाली आबादी में वृद्धि देख रहा है जो वर्ष 2040 तक अपने चरम पर पहुंच सकती है।

जनसांख्यिकी की स्थिति

- राज्यों में उनकी जनसांख्यिकीय रूपरेखा और विकास के बीच बड़ी विषमताएं है। जबकि प्रायद्वीपीय राज्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन भीतरी राज्य बढ़ती कार्यशील आयु वाली जनसंख्या के साथ अपेक्षाकृत युवा और सक्रिय हैं।
- इस जनसांख्यिकीय क्षमता के लाभ के लिए युवा श्रम बल को अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार हेतु नियोजित कौशल और ज्ञान युक्त होना चाहिए।
- व्हीबॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2018, दर्शाती है कि उच्च शिक्षा संस्थानों से आने वाले केवल 46% युवा ही रोजगार पाने योग्य हैं। यह कौशल के अंतर; कौशल विसंगति या कौशल की कमी से संबंधित मुद्दों को उठाता है।
- एन.एस.डी.सी द्वारा कौशल की कमी पर कराए गए एक अध्ययन का अनुमान है कि अर्थव्यवस्था के 24 प्रमुख क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक 109.73 मिलियन कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है।
- युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उद्यमिता का वातावरण मजबूत करने की त्वरित आवश्यकता है।

मुख्य चुनौतियां:

- कम शिक्षित युवाओं की बड़ी संख्या।
- कम रोजगार के साथ कुशल जनशक्ति की ऊंची मांग।
- औपचारिक स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने वालों को कौशल प्रदान करते हुए बुनियादी अंकज्ञान, साक्षरता और व्यवहारिक कौशल हासिल करने का दूसरा मौका देना ताकि वे औपचारिक क्षेत्र में नौकरियों प्राप्त कर सकें।
- युवाओं की तुलना में प्रशिक्षण क्षमताओं का सीमित और असमान वितरण।
- प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उनके लिए कैरियर विकास के मार्गों पर ध्यान न देने के कारण अच्छी गुणवत्ता वाले प्रशिक्षकों की उपलब्धता।
- मूल्यांकन और प्रमाणन प्रणालियों की अधिकता, जो असंगत परिणामों और नियोक्ताओं को भ्रम की ओर ले जाती है।
- अनौपचारिक / असंगठित क्षेत्र की प्रबलता और मौजूदा कौशल एवं आवश्यक कौशल का पता लगाना।

gradeup

- क्षेत्रों में मेल और समन्वय हासिल करना।

<u>प्रशासन संरचना में परिवर्तन:</u>

- कौशल विकास एवं उद्यमिता समर्पित एक मंत्रालय की स्थापना नवंबर, 2014 में भारत में सभी कौशल विकास गतिविधियों के एक नोडल मंत्रालय के रूप में की गई थी।
- उद्यमिता पर केंद्रित एक नई योजना- "राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता योजना" वर्ष 2015 में शुरू की गई थी।

<u>व्यवस्थागत हस्तक्षेप:</u>

- सूचना की उपलब्धता में सुधार, दक्षता के प्रशिक्षण और मानकीकरण के वितरण में तालमेल के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
- मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष दोनों की जानकारी एक जगह उपलब्ध कराने के लिए एक श्रम बाजार सूचना प्रणाली स्थापित की गई है। यह सभी हितधारकों की मदद करने के लिए एकल स्रोत है।
- मंत्रालयों और राज्यों में कौशल विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में तालमेल बिठाने के लिए, सामान्य मानदंडों को अधिसूचित किया गया है।
- एक योग्यता-आधारित फ्रेमवर्क एन.एस.क्यू.एफ ने गैर-औपचारिक कौशल की पहचान को मंजूरी दी है।

<u>प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि:</u>

- आई.टी.आई की संख्या मई, 2014 में 10,750 से बढ़कर मई, 2018 में 14,276 हो गई है।
- अल्पकालिक प्रशिक्षण भी वर्ष 2013-14 के 3.34 लाख से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 16 लाख हो गया है।
- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई) केंद्र विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैले हुए हैं और प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाते हैं।
- भारतीय श्रमिकों की गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए, प्रधान मंत्री कौशल केंद्रों के संदर्भ में बहुकौशल संस्थान 460 जिलों में स्थापित किए गए हैं और अन्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
- कौशल सामग्री और पाठ्यक्रम के प्रसार के लिए ई-मार्केटप्लेस और ऐप आधारित पुस्तकालय शुरु किए गए हैं।

<u>गुणवत्ता और प्रासंगिकता में वृद्धि</u>

- प्रशिक्षण परिणाम में गुणवत्ता मानदंडों को सुधारने और लागू करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। 5,000 से अधिक आई.टी.आई और 15,000 प्रशिक्षण केंद्रों को वर्गीकृत किया गया है।
- प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्मार्ट (SMART) पोर्टल के माध्यम से समवर्ती निगरानी हेतु एक प्रणाली शुरू की गई है।
- बेहतर गुणवत्ता के प्रयासों से शुल्क आधारित प्रशिक्षण (26 से 50%) और अनुदान आधारित प्रशिक्षण (पी.एम.के.वी.वाई) (17 से 60%) दोनों के प्लेसमेंट प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

gradeup

अनौपचारिक कौशल को औपचारिक रूप देना: प्राथमिक शिक्षा को मान्यता और अप्रेंटिसशिप

- अनौपचारिक कामगारों की सुविधा और अनौपचारिक क्षेत्र की कौशल आवश्यकता का पता लगाने के लिए एक कार्यक्रम "रिकग्नीशन ऑफ प्रायर लर्निंग" शुरु किया गया है जिससे कामगारों के कौशल का परीक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाता है।
- प्रशिक्षु मॉडल एक उद्योग कामगारों के सृजन की ओर जाता है।
- दुनिया भर के अधिकांश देशों ने प्रशिक्षु मॉडल लागू किया है - जापान में 10 मिलियन से अधिक प्रशिक्षु हैं, जर्मनी में 3 मिलियन प्रशिक्षु हैं और अमेरिका में 0.5 मिलियन प्रशिक्षु हैं, जबकि भारत में केवल 0.3 मिलियन प्रशिक्षु हैं।
- अप्रेंटिसशिप को कौशल विकास के तरीके के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए, वर्ष 2014 में अपरेंटिसशिप एक्ट, 1961 में संशोधन किया गया था ताकि प्रशिक्षुओं के दायरे को बढ़ाया जा सके। प्रशिक्षु चक्र को सुविधाजनक बनाने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।
- ऐसा माना जाता है कि इस तरह की पहलों से भारत को विश्व की कौशल राजधानी में बदला जाएगा।

कौशल अधिग्रहण को आकांक्षी बनाना

- व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़े सामाजिक कलंक की वजह से कौशल बहुत आकांक्षी नहीं है।
- विश्व कौशल प्रतियोगिता और क्षेत्रीय स्तर की कौशल प्रतियोगिताओं में भागीदारी ने पहचान प्राप्त करने और उत्कृष्टता दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया है।
- आई.टी.आई और कौशल केंद्रों को प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार उपाधि वितरण समारोह आयोजित किए गए हैं।

gradeup

भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाना

- भारतीय श्रमिकों की गतिशीलता वैश्विक स्तर पर सुविधाजनक बनाने के लिए एम.एस.डी.ई ने पूर्व प्रस्थान अभिविन्यास और बुनियादी भाषा कौशल के साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एम.ई.ए इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर स्थापित किए हैं।
- जापान के साथ तकनीकी इंटर्नशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किए गए हैं।

सूक्ष्म उद्योगों को बाजार से जोड़ना

- प्रौद्योगिकी आने से गांव स्तर पर बड़े बाजार स्थानों पर अधिक सूक्ष्म उद्यम तैयार करने और उन्हें जोड़ने से पलायन सीमित हो सकता है और सतत आजीविका की संभावना बढ़ सकती है।
- स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण के लिए पी.एम.के.वी.वाई के राज्य घटक को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

कौशल से पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी

- भारतीय उद्योगों में कुशल श्रम के लिए पारिश्रमिक वृद्धि अभी भी यथार्थ नहीं है क्योंकि अधिकांश उद्योग लागत पर केंद्रित हैं और इस प्रकार कुशल श्रमिकों का लाभ समझने में असमर्थ हैं।
- किसी भी प्रकार की पारिश्रमिक लाभ की कमी छात्रों को कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के बजाय सीधे अकुशल श्रम के रूप में रोजगार तलाशने और नौकरी करने का कारण बनती है।

<u>निजी क्षेत्र से वित्त को प्रोत्साहित करना</u>

- यद्यपि उद्योग कुशल जनशक्ति का प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं, लेकिन कौशल पहल को पूर्णतया सरकारी पहल से वित्त पोषित किया गया है।
- उद्योगों की कौशल विकास गतिविधियों में स्वैच्छिक सहभागिता को प्रेरित करने हेतु हमें प्रतिपूर्ति योग्य योगदान, शुल्क या अनिवार्य उपकर जैसे विभिन्न विकल्पों का पता लगाने की आवश्यकता है।

gradeup

एम.एस.एम.ई (MSMEs): वृद्धि और विकास के नए वाहक

परिचय:

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (**MSMEs**) क्षेत्र निरंतर भारत की सकल सार्थक सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
- यह न केवल स्व-रोजगार प्रदान करता है वरन इसमें नौकरियों के अवसर पैदा करने की भी संभावनाएं हैं। एम.एस.एम.ई को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है।
- एम.एस.एम.ई मंत्रालय ने उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने और स्व-रोजगार और नौकरी सृजन के लिए प्रमुख अवसर पैदा करके इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

एम.एस.एम.ई: रोजगार सृजन:

- वर्तमान में कार्यरत 7 करोड़ से अधिक एम.एस.एम.ई देश में विभिन्न प्रकार के उद्यमों में लगभग 12 करोड़ नौकरियां पैदा कर रहे हैं।
- यह क्षेत्र कृषि क्षेत्र के बाद स्व-रोजगार के साथ-साथ नौकरियों के अवसरों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। एम.एस.एम.ई के लिए श्रम-पूंजी अनुपात बहुत अधिक है।
- चूंकि देश आने वाले वर्षों में कार्यशील आयु वाली आबादी में अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि और विस्तार का साक्षी बनने जा रहा है, इसलिए एम.एस.एम.ई क्षेत्र को इस श्रम बल को आत्मसात करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
- मानव पूंजी के सृजन पर अधिक ध्यान देना महत्वपूर्ण है, विशेषकर कुछ विनिर्माण उद्योगों में जो श्रम पर अत्यधिक बल देने वाले हैं।

कार्यवाही हेतु कार्यसूची:

- एम.एस.एम.ई क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।
- विनिर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था में अन्य क्षेत्रों से कच्चे माल और सेवाएं लेकर बदले में उन्हें तैयार उत्पाद सामग्री उपलब्ध करता है, इस प्रकार कच्चे माल से मध्यवर्ती वस्तुओं तक की सभी वस्तुओं की मांग को बढ़ाता रहता है।
- राष्ट्रीय निर्माण नीति (एन.एम.पी) के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2022 तक 100 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता है।
- रोजगार वृद्धि के संबंध में कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:
  - श्रम-प्रधान उद्योगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
  - स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नवाचार प्रयोगशालाओं की स्थापना करके प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाना।
  - सर्वोत्तम अभ्यास अपनाकर श्रम उत्पादकता में वृद्धि करना।

gradeup

- समय पर ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- अच्छे बाजार तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना।

- भारत को रोजगार मांगने वालों का देश बनाने के स्थान पर रोजगार का सृजन करने वाला देश बनाने के सपने को साकार करने के लिए एम.एस.एम.ई मंत्रालय के पास उद्यमशीलता को समर्थन प्रदान करने वाला एक केंद्रित दृष्टिकोण है।
- इसलिए, सरकार द्वारा देश भर में इस क्षेत्र के उन्नयन और विकास के लिए कई योजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना (पी.एम.ई.जी.पी) और मुद्रा, और पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने हेतु कोष योजना (एस.एफ.यू.आर.टी.आई)।

<u>बाजार तक पहुंच में बढ़ोत्तरी:</u>

- एम.एस.ई के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाने और समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए, सरकार की लोक क्रय नीति (पी.पी.पी) उद्यमिता की ओर एक अभियान चला रही है।
- एक आज्ञा-पत्र में कहा गया है कि सी.पी.एस.ई, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य सरकारी विभागों द्वारा माल एवं सेवाओं की कुल खरीद का 20% एम.एस.ई से किया जाएगा, जिसमें से 4% उद्यम अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एम.एस.ई से होंगे।
- मंत्रालय का **एम.एस.एम.ई संबंध पोर्टल** माल और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद में भाग लेने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमियों सहित एम.एस.ई की मदद कर रहा है।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए पी.पी.पी को प्रभावी रूप से व्यक्त करने के लिए, वर्ष 2016 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति केंद्र (एन.एस.एस.एच) शुरु किए गए थे।

<u>सही समय पर ऋण प्राप्ति:</u>

जहां तक एम.एस.एम.ई मंत्रालय का सवाल है, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना (पी.एम.ई.जी.पी) के बजट आवंटन में लगभग 80% की वृद्धि हुई है।

- मुद्रा के लिए, केंद्रीय बजट में यह घोषणा की गई थी, कि 3 लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट प्रवाह लक्ष्य; लगभग 5 करोड़ खातों को वित्त पोषित किया जाएगा।
- ऋण गारंटी कोष (सी.जी.टी.एम.एस.ई) में 2500 करोड़ रुपये से 8000 करोड़ रुपये से अधिक तक की वृद्धि करना है।
- मिशन सौर चरखा के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में 50 क्लस्टर्स स्थापित करने की कल्पना की गई है।
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी) ऋण प्रवाह, बहुत प्रतिस्पर्धी दरों पर कच्चे माल की आपूर्ति और एम.एस.एम.ई को प्रशिक्षण और उद्भवन की सुविधा प्रदान करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

gradeup

<u>प्रोत्साहन:</u>

- वित्तीय परिप्रेक्ष्य से, वर्ष 2014-18 के दौरान बजटीय समावेशन में सरकार द्वारा प्रदान की गई प्रोत्साहन राशि में 41% की वृद्धि देखी जा सकती है।
- सी.जी.टी.एम.एस.ई, पी.एम.ई.सी.पी, एस.एफ.यू.आर.टी.आई ने क्रमश: 51.11 लाख, 14.78 लाख और 0.60 लाख रोजगारों के सृजन में योगदान दिया।
- एम.एस.एम.ई मंत्रालय के देश भर में 18 उपकरण कक्ष हैं और 15 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इससे अधिक उद्यमियों और नौकरी तलाशने वालों को प्रशिक्षण देने में मदद मिलेगी। वर्तमान में, इन 18 उपकरण कक्ष में लगभग 1.5 लाख नौकरी तलाशने वाले लोग प्रशिक्षित किए जा रहे हैं।
- यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नौकरियों का सृजन करते समय सामाजिक समावेश के प्रति ध्यान केंद्रित किया गया हो। पी.एम.ई.जी.पी के तहत, 30% अर्थात 4.43 लाख लाभार्थी महिलाएं थीं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति (एस.सी) और अनुसूचित जनजाति (एस.टी) समुदायों से संबंधित क्रमश: 1.74 लाख और 1.31 लाख व्यक्तियों को इस कार्यक्रम के तहत पिछले 4 वर्षों के दौरान नियोजित किया गया है।

<u>निष्कर्ष:</u>

- पिछले एन.एस.एस.ओ सर्वेक्षण के अनुसार, देश में लगभग 6.34 करोड़ एम.एस.एम.ई हैं।
- जी.एस.टीएन में पंजीकृत अधिकांश इकाइयां एम.एस.एम.ई हैं।
- इस तरह की पहल के साथ, भारत ने एक नई धारा की अर्थव्यवस्था शुरू की है क्योंकि इसने एम.एस.एम.ई की संभावना को विकास और रोजगार सृजन के नए इंजन के रूप में स्वीकार किया है।

gradeup

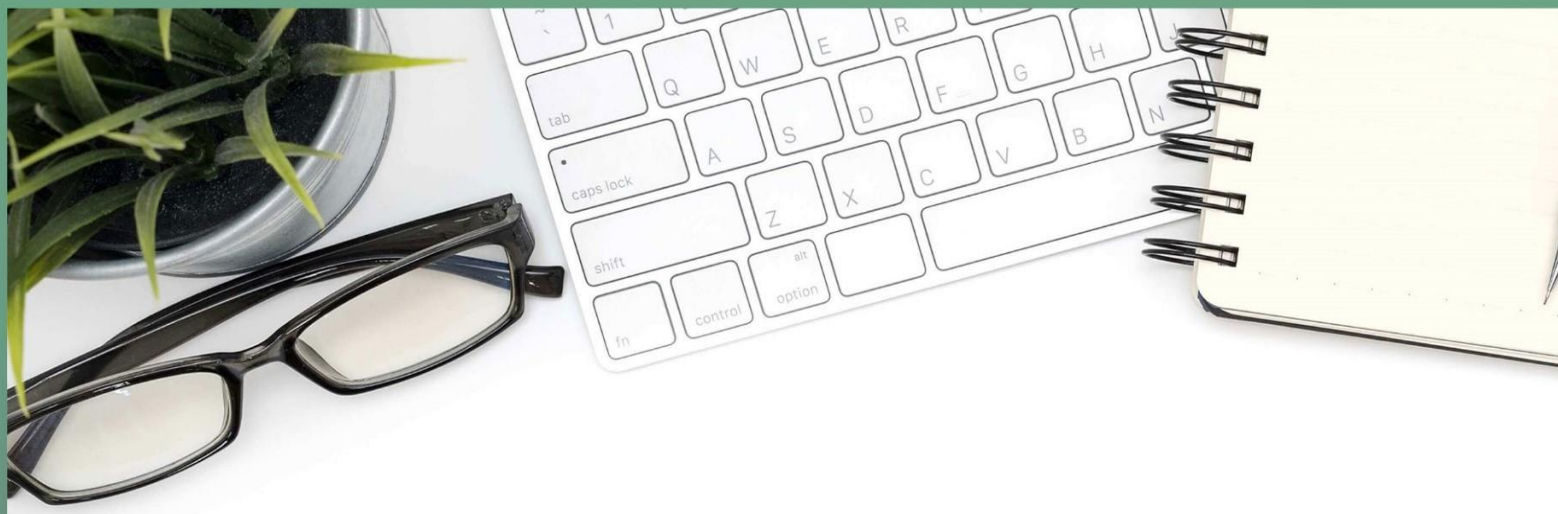

बैंकिंग, एसएससी, गेट, सीटीईटी, जेईई एवं अन्य प्रवेश परीक्षाएं

- नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित
- हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है
- अखिल भारतीय रैंक और परिणाम विश्लेषण प्राप्त करें
- विस्तृत समाधान

ANDROID APP ON Google play